MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED LOSS OF FILE CONTAINING DOCUMENTS RELATING TO THE TIME-CAPSULE

श्री केशव राव धोंडगे (नान्देड़) : सदर साहब, मैं नियम 377 के द्वारा एक अहमियत का सवाल उठाना चाहता हूं।

कालपात्र के बारे में महत्वपूर्ण कागजात और फाइलें भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद के मुख्यालय से गायब हो चुके हैं। यह बड़ा गम्भीर मसला है। ये कागजात जिस दिन यह मसला लोक सभा में चर्चा के लिए आया उसी दिन गुम हो गए हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वह इस पर स्टेटमेंट करने का साहस करें। जय क्रान्ति।

(ii) REPORTED MOVE TO WIND UP THE JUTE CORPORATION OF INDIA AT CALCUTTA

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, under Rule 377, I rise to draw the attention of the House to the reported move to wind up the Jute Corporation of India at Calcutta.

In the Economic Times of April 11, it was reported that the Government is contemplating to wind up the Jute Corporation of India with its headquarters at Calcutta and assign its function of price support operations to the Food Corporation of India which is supposed to have experience in similar operations. This will be a disastrous step not only for 1000 employees of the Jute Corporation of India but also for the jute growers in the jute growing States of West Bengal, Bihar, Assam, Arissa and Tripura for whose benefit the Jute Corporation of India was set up.

The Jute Corporation of India has already established about a hundred direct purchase centres to purchase jute from the growers. If the Corporation has not been able to give adequate relief to jute growers, if it has not been able to save them from exploitation, it is not because of some inherent fault in the Corporation but it is because of the incapacity of the present management and the wrong pricing policies taken up by successive Governments. The successive governments have always not paid the jute growevrs adequate price and the Agricultural Prices Commission has never been favourable to the jute growers. So, this extreme step to wind up the Jute Corporation is not called for and I want to request the Government not to consider this step at all.

(iii) ADVERSE EFFECT OF POWER SHORTAGE ON AGRICULTURE AND INDUSTRIAL PRODUCTION

श्री वीरेन्द्र प्रसाद (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि :

"समस्त भारत में बिजली के अभाव में खेती एवं उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा रहा है। उत्पादन को जबरदस्त धक्का लग रहा है। उत्पादन के अभाव में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, साथ साथ मजदूरों के सामने भी समस्या खड़ी होती है। विशेष कर बिहार राज्य में बिजली के अभाव में खेती एवं उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। किसानों में हाहाकार मचा है। जितने मेगावाट बिजली का उत्पादन है उससे ज्यादा बिजली विभाग ने बिजली देने का ऐग्रीमेंट करा रखा है। यद्यपि बिजली की आपूर्ति नहीं होती फिर भी उपभोक्ताओं से मिनिमम गारन्टी ली जाती है जिससे उपभोक्ताओं में काफी क्षोभ है। सरकार को इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति तय करनी चाहिये कि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गारन्टी मिले। यदि बिजली आपूर्ति की गारन्टी नहीं है तो मिनिमम गारन्टी